

नए ई-अपशिष्ट नियम नौकरियों, संग्रह नेटवर्क को धमकी देते हैं

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर-II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप), जीएस पेपर-III (पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट)

सरकार ने भारत में ई-कचरे को विनियमित करने के लिए एक नए ढांचे का प्रस्ताव किया है जो अनौपचारिक क्षेत्रों को परेशान कर सकता है।

ई-अपशिष्ट नियमों पर मसौदा अधिसूचना में उत्पादक जिम्मेदारी संगठन (पीआरओ) और प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ निहित रीसाइक्लिंग की सभी जिम्मेदारी के साथ विघटित करने वालों को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

E-WASTE के बारे में

- ई-अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों (ईईई) और इसके भागों की सभी वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें उनके मालिक द्वारा पुनः उपयोग के इरादे के बिना अपशिष्ट के रूप में छोड़ दिया गया है।

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका (ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020) के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा जनरेटर है।

- इसे दो व्यापक श्रेणियों के तहत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण.
- उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स.

- घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से अपशिष्ट को अलग करने, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक **भोपाल, मध्य प्रदेश** में स्थापित किया गया है।

इस मुद्दे के बारे में

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत, संगठन के लिए **ई-कचरे के पुनर्चक्रण की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी का पालन करना** अनिवार्य है। इसका अनुपालन करते हुए, अधिकांश फर्मों ने **निर्माता जिम्मेदारी संगठन (पीआरओ)** नामक संगठनों को रीसाइक्लिंग आउटसोर्स किया (सीपीसीबी ने 74 पीआरओ पंजीकृत किए हैं)
- इस साल मई में, पर्यावरण मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की जो **पीआरओ और डिसप्लेसर को समाप्त कर देती है** और **अधिकृत रीसाइक्लरों** के साथ रीसाइक्लिंग की सभी जिम्मेदारी निहित करती है, जिनमें से केवल कुछ मुट्टी भर भारत में मौजूद हैं।
- अब, **अधिकृत रीसाइक्लर अपशिष्ट की एक मात्रा का स्रोत बनाएंगे, इसे रीसायकल करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र उत्पन्न करेंगे।** कंपनियां इन प्रमाणपत्रों को अपने वार्षिक प्रतिबद्ध

लक्ष्य के बराबर खरीद सकती हैं और इस प्रकार उन्हें पीआरओ और विखंडनकर्ताओं को शामिल करने के साथ शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

लाभ

- प्रणाली को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करें।
- एक इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन प्रणाली शुरू करें जो रीसाइक्लिंग के लिए जाने वाली सामग्री को ट्रैक करेगी।
- रीसाइक्लिंग लाभकारी बनाएं: वर्तमान में, पूरी प्रणाली recyclers के लिए लाभकारी नहीं है, जो रीसाइक्लिंग का काम करते हैं।
- विश्वसनीयता बढ़ाएं: प्रो द्वारा प्रबंधित वर्तमान प्रणाली हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है क्योंकि डबल-काउंटिंग के कई उदाहरण हैं (जहां एक कंपनी के लिए एक बार पुनर्नवीनीकरण किए गए समान लेख कई कंपनियों के लिए खाते में जमा किए जाते हैं)।

इस कदम के खिलाफ आपत्तियां

- नौकरी खोना: कई पीआरओ ने पर्यावरण मंत्रालय को अपनी आपत्तियों को यह तर्क देते हुए मेल किया है कि एक नवोदित प्रणाली को समाप्त करना भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन के भविष्य और नौकरी के नुकसान के लिए हानिकारक था।

ज्स्थापित पीआरओ के लिए निवेश की हानि।

- जवाबदेही की हानि: पीआरओ अनधिकृत रीसाइक्लिंग के खिलाफ जांच और संतुलन प्रदान करते हैं।

मसौदा नियम के अन्य प्रावधान

- कवरेज: यह विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) फ्रेमवर्क के तहत निर्माता, उत्पादक, रीसायकलर और रिफर्बिशर्स को कवर करता है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे।
- ईपीआर एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता के बाद के उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी-वित्तीय/भौतिक-दी जाती है।
- लक्ष्य: उपभोक्ता वस्तु कंपनियों और निर्माताओं को 2022-23 तक ईपीआर योजना में दर्शाए गए ई-अपशिष्ट उत्पादन का कम से कम 60%, 2023-24 तक 70% और 2024-25 के बाद से 80% सुनिश्चित करना होगा।

ज्ईपीआर प्रमाण पत्र सृजन सीपीसीबी द्वारा पुनर्चक्रण और नवीकरण के लिए पोर्टल के माध्यम से।

-

ट्रेडिंग: कार्बन क्रेडिट के समान प्रमाण पत्रों में व्यापार की एक प्रणाली को प्रभाव में लाएं, जो कंपनियों को अस्थायी रूप से कमी को दूर करने की अनुमति देगा।

भारत की 'गेहूं माफी' डब्ल्यूटीओ की मांग

पाठ्यक्रम: जीएस पेपर-III (अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव)

संदर्भ: हाल ही में, भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से मांग की कि भोजन के सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) के मुद्दे का स्थायी समाधान निकाला जाए।

पृष्ठभूमि

- उपज की खरीद के लिए भारत की **एमएसपी नीति** (किसानों की आय का समर्थन करने के साथ-साथ गरीबों के लिए सब्सिडी वाला भोजन प्रदान करने के लिए) डब्ल्यूटीओ के नियमों से बाहर हो गई थी।
 - भारत की पीएसएच नीति दो उद्देश्यों को पूरा करती है:
 1. किसानों को लाभकारी मूल्य की पेशकश
 2. वंचितों को राजसहायता प्राप्त भोजन प्रदान करना.
 - डब्ल्यूटीओ कानून के तहत, किसानों से इस तरह की मूल्य समर्थन-आधारित खरीद को **व्यापार-विकृत करने वाली सब्सिडी** माना जाता है।
 - वर्तमान में, भारत के पास एक '**शांति खंड**' के कारण अस्थायी राहत है जो देशों को इन सब्सिडी के खिलाफ कानूनी चुनौतियों को उठाने से रोकता है।
- ज् विश्व व्यापार संगठन का शांति खंड (बाली मंत्रिस्तरीय, 2013 में अंतःस्थापित) राजसहायता सीमा का उल्लंघन होने की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों से कार्रवाई के विरुद्ध भारत के खाद्य खरीद कार्यक्रमों की रक्षा करता है।
- भारत की चिंता यह है कि डब्ल्यूटीओ के पास एमएसपी का उपयोग करके सार्वजनिक खाद्य भंडार रखने के लिए नीतिगत स्थान होना चाहिए। हालांकि **जिनेवा घोषणा** में मूल्य समर्थन का कोई उल्लेख नहीं है।

क्या देश सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग खाद्यान्नों का निर्यात कर सकता है?

ज् विश्व व्यापार संगठन देशों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खरीदे गए खाद्यान्नों के निर्यात से रोकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि:

- a. वैश्विक कृषि व्यापार में एक **अनुचित लाभ** देता है।
 - b. एक देश बहुत कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्यान्न बेचेगा। इससे **वैश्विक कीमतों में गिरावट** आएगी और **अन्य देशों के कृषि व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ेगा।
- तदनुसार, **खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए पीएसएच पर 2013 के डब्ल्यूटीओ निर्णय के पैरा 4 में, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए खाद्य की खरीद करने वाले देश यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के**

खरीदे गए खाद्य "व्यापार को विकृत न करें या अन्य सदस्यों की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें"।

- यह जिनेवा मंत्रिस्तरीय खाद्य सुरक्षा घोषणा के पैरा 10 में भी परिलक्षित होता है। घोषणा में कहा गया है कि देश डब्ल्यूटीओ कानून के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिशेष खाद्य भंडार जारी कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ कुछ देशों में चल रहे खाद्य संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से गेहूं के निर्यात की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी छूट के लिए सहमत हो सकता है।

हाल ही में WTO मंत्रिस्तरीय बैठक में PSH की स्थिति

- पीएसएच नीति के स्थायी समाधान की भारत की मांग ने हाल ही में डब्ल्यूटीओ की बैठक में एक नया आयाम हासिल किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने कई देशों में खाद्य संकट पैदा कर दिया है।
- भारत इस बात पर जोर देता है कि उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीदे गए खाद्यान्नों के पूल से खाद्य, विशेषरूप से गेहूं के निर्यात की भी अनुमति दी जानी चाहिए।

भारत अपनी पीएसएच नीति की रक्षा के लिए क्या कर सकता है?

- जू भारत को अपनी सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से गेहूं के निर्यात में छूट की मांग करने के संबंध में अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए। अन्य देशों में खाद्य संकट की मदद के लिए, भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकता है।
- भारत को खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने पीएसएच कार्यक्रम के लिए स्थायी समाधान पर जोर देने के अपने मुख्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत गेहूं निर्यात के लिए निजी व्यापारियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा सकता है।

प्रीलिम्स तथ्य

अल्फा तह

- यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरण है, जिसे डीपमाइंड टेक्नोलॉजीज (Google बहन कंपनी) द्वारा विकसित किया गया है, जिसने लगभग सभी प्रोटीनों की संरचनाओं की भविष्यवाणी और प्रकाशित की है।
- प्रोटीन को आमतौर पर जीवन के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है, जो अमीनो एसिड के संयोजन से बना होता है।
- शोधकर्ता स्थिरता, खाद्य असुरक्षा और उपेक्षित बीमारियों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए अल्फा फोल्ड का उपयोग कर सकते हैं।

आण्विक मोटर

- वैज्ञानिकों ने **डीएनए ओरिगामी विधि का उपयोग करके एक आणविक पैमाने पर मोटर का निर्माण किया है** (नैनोस्केल पर 2 डी और 3 डी वस्तुओं को बनाने के लिए डीएनए की तह शामिल है)।
- आणविक मोटर्स प्रोटीन का एक वर्ग है जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करके **इंट्रासेल्युलर आंदोलन को चलाता है**।
- हमारे शरीर में आणविक मोटर्स की भूमिका के कुछ उदाहरण **मांसपेशियों के संकुचन, माइटोसिस सेल विभाजन आदि हैं**।

सैन्य अभ्यास

- **अल NAJAH-IV**: यह **भारतीय सेना और ओमान की रॉयल आर्मी** के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **पूर्व VINBAX**: यह **भारत और वियतनाम** के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।

समाचार में आक्रामक प्रजातियां

विलायती किकर: दिल्ली अपने केंद्रीय रिज की पारिस्थितिक बहाली को लागू कर रही है जिसमें **आक्रामक प्रजातियों विलायती किकर (प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा) को स्वदेशी प्रजातियों के साथ बदलना शामिल है**।

दक्षिण और मध्य अमेरिका के मूल निवासी, इसे अंग्रेजों द्वारा ग्रामीण गरीबों की **ईंधन और लकड़ी की आवश्यकता** को पूरा करने के साथ-साथ अवक्रमित भूमि को बहाल करने के लिए भारत में पेश किया गया था।

इसने शुष्क परिस्थितियों में **गुणों-विकास की तरह खरपतवार किया है**, किसी भी प्रतियोगिता को मार दिया है, और पानी की मेज में कमी आई है।

NEW LEASE OF LIFE
Central ridge is spread **over 864 hectares**
423 hectares to be restored over 5 years
COST ₹12.6 crore

THE PROJECT
➤ The 'invasive' vilayati kikar and lantana to be replaced by native species
First phase of restoration: Between SP Marg and Vande Mataram Marg

HOW IT WILL BE DONE
➤ Native tree species to be planted around vilayati kikar
➤ Canopy openings to be created to allow sunlight to reach the forest floor
➤ Creepers to be used on vilayati kikar to naturally 'strangulate' it
➤ The dead tree will then be removed, once native species around it grow to a certain height

Map labels: Vande Mataram Marg, CENTRAL RIDGE, SP Marg, Rashtrapati Bhawan

अमेरिकी बुलफ्रॉफ और ब्राउन ट्री स्नेक: हाल के एक अध्ययन के अनुसार, इन प्रजातियों ने 1986 और 2020 के बीच दुनिया को अनुमानित \$ 16 बिलियन की लागत दी, जिससे फसल क्षति से लेकर बिजली की कमी तक की समस्याएं पैदा हुईं।



ओरुनुदोई योजना

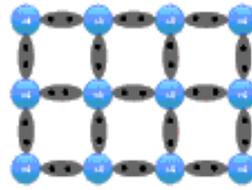
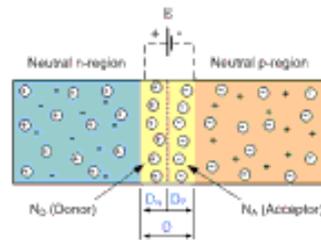
- असम में ओरुनुदोई योजना के कुछ 22 लाख लाभार्थियों को राष्ट्रीय ध्वज या दो खरीदने के लिए अगस्त के लिए 18 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
 - असम सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में शुरू की गई, ओरुनुदोई योजना राज्य की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है।
- इस योजना के तहत असम के हाशिए पर पड़े परिवारों की महिला सदस्यों को 1,000 रुपये की मासिक सहायता हस्तांतरित की जाती है।
- एक डीबीटी, या एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना होने के कारण, पैसा सीधे एक परिवार की महिला प्रमुख के बैंक खाते में जमा किया जाता है क्योंकि वे "घर के प्राथमिक देखभालकर्ता" हैं।
 - यह योजना "गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक विकल्प देती है कि वे अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहते हैं।

गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-2027

- गुजरात एक समर्पित अर्धचालक नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है।
- सरकार ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में एक विशेष 'सेमीकॉन सिटी' विकसित करने का भी प्रस्ताव किया है।
- गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 के तहत, गुजरात सरकार उन उद्यमियों के लिए बिजली, पानी और भूमि टैरिफ पर भारी सब्सिडी प्रदान करेगी जो गुजरात में अर्धचालक या प्रदर्शन निर्माण विनिर्माण में निवेश करने में रुचि रखते हैं।
- एक अर्धचालक एक पदार्थ है जिसमें एस पेसिफिक विद्युत गुण होते हैं जो इसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक नींव के रूप में सेवा करने में सक्षम बनाते हैं। यह

आमतौर पर एक ठोस रासायनिक तत्व या यौगिक है जो कुछ शर्तों के तहत बिजली का संचालन करता है लेकिन दूसरों को नहीं।

What is a Semiconductor?



 **Electrical 4 U**

Microsoft*
TranslatorX
Original

The draft notification on e-waste rules proposes to do away with Producer Responsibility Organization (PRO) and dismantlers with all responsibility of recycling vested with authorized recyclers.